

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 57/23

GCMS NO 2023/118

हरिप्रसाद पुत्र राधेश्याम निवासी जयलालपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर  
अपीलांत

बनाम

1. मोहनलाल
2. हरगोविन्द
3. मदनलाल
4. शम्भूदयाल पुत्रान रामसहाय जातियान ब्राह्मण निवासीयान जयलालपुरा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

( अपील विरुद्ध मु0न0 24/20 निर्णय दिनांक 3.7.23 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली)  
अभिभाषक अपीला0 श्री रघु बंसल  
अभिभाषक रेस्पो0 श्री बालकृष्ण उपाध्याय


दिनांक 19.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 3.7.23 न्यायालय उपजिला कलेक्टर, बौली पेश की है ।


अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीयान की पुश्तैनी आराजी ख0न0 837,838,839,840,841 कुल किता 5 कुल रकबा 2.03 है0 वाके ग्राम जयलालपुरा है जिस पर प्रार्थीगण काश्त कर अपने परिवार का जीवकोपार्जन करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के पास अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 848 है जिसकी पूर्वी मेर के सहारे प्रार्थीयान अपने उक्त खेतो पर आते जाते है। लेकिन प्रार्थीयान को दिनांक 11.6.20 को अप्रार्थीयान ने मेर के सहारे आने जाने से रोका। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया। अतः प्रार्थीयान की आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थीयान की आराजी ख0न0 848 की पूर्वी मेर से आने जाने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ प्रार्थीयान/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीयान/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांत/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर




अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो० ने अनुतोष चाहा है कि स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की फरमाई जावे की अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी ख०न० 848 की पूर्वी मेर के सहारे प्रार्थीगण/रेस्पो० की खातेदारी ख०न० 840 तक हमेशा की तरह रास्ते का खुलासा रखें एवं उसमें प्रार्थीगण/रेस्पो० को आने जाने में किसी प्रकार की कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करे। यह कि नक्शा ट्रेस में ख०न० 848 से 840 तक जो रास्ता दर्शाया गया है जिसमें यह नम्बर अंकित नहीं है उसमें नवीन नम्बर डलवाया जावे जिससे रास्ते को नवीन नम्बर से जाना जावे। पैरा संख्या 2 में वर्णित अनुतोष रा०का०अधि० की धारा 251 ए के तहत दिया जाना कानूनन संभव नहीं है। उक्त अनुतोष के लिए रा०का०अधि० में अलग से प्रावधान है। रेस्पो० ने पूर्व से मौजूद कथित रास्ते पर बाधा उत्पन्न नहीं किये जाने व इन्द्राज दुरुस्ती का अनुतोष चाहा है जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो० के अनुतोष से अलग अपीलांट के खातेदारी की भूमि ख०न० 848 से रास्ता दिये जाने का व उस रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का अनुतोष बिना मांगे दिया गया है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मांगे गये अनुतोष से अलग अथवा अधिक अनुतोष किया जाना गैर कानूनी है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। यह स्वीकृत तथ्य है कि ख०न० 848 अपीलांट की रिकार्डेड खातेदारी की कृषि भूमि है। रेस्पो० ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह अंकित किया है कि उक्त भूमि की पूर्वी मेर से होकर डोटेड लाईन से रास्ता नक्शा ट्रेस में दिखा रखा है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय से इस तथ्य पर गौर नहीं किया है। उक्त डोटेड लाईन से रास्ता किस राजस्व अधिकारी के आदेश से अंकित किया है। इससे यह भलि भांति प्रमाणित है कि रेस्पो० ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से साज कर अपीलांट की रिकार्डेड खातेदारी की भूमि ख०न० 848 डोटेड लाईन दर्ज की है। जिसके संबंध में अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में तरमीम दुरुस्ती का दावा प्रस्तुत कर रखा है। जो अभी लंबित है। आक्षेपित आदेश से उक्त दावा प्रस्तुत करने का मकसद ही विफल हो जावेगा। अपीलांट के खेत ख०न० 848 की मेर से रेस्पो० का कभी भी रास्ता नहीं रहा है। रेस्पो० उनकी खातेदारी के खेत ख०न० 838 के दक्षिण और स्थित चारागाह भूमि से होकर आते जाते रहे हैं। रेस्पो० गिरोहबंद लठठबाज व्यक्ति है जो अपीलांट से रंजिशवश नुकसान पहुँचाने की गरज से अपीलांट की जमीन से रास्ता मांग रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो० द्वारा रास्ता खुलासा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा था जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नया रास्ता दर्ज कर कानून के खिलाफ जाकर निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में यह विरोध किया था कि रास्ते के विवाद में लैण्ड होल्डर आवश्यक पक्षकार है। जिसके असंयोजन के कारण दावा रेस्पो० खारिज होने योग्य है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। रेस्पो० अपीलांट की खातेदारी की आराजी ख०न० 848 की पूर्वी मेर से रास्ता चाहते हैं जितनी जमीन अपीलांट की भूमि से रास्ते के लिए आवश्यक है, उतनी ही भूमि अपीलांट की ख०न० 848 के संटवा स्थित रेस्पो० की आराजी ख०न० 840 रकबा 0.5000 है० अथवा आराजी ख०न० 841

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

रकबा 0.5000 है० मे से अपीलांट को देकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा दी जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।


रेस्पो० ने अपील की बहस मे तर्क दिया कि रेस्पो०/प्रार्थीयान की पुश्तैनी आराजी ख०न० 837,838,839,840,841 कुल किता 5 कुल रकबा 2.03 है० वाके ग्राम जयलालपुरा है जिस पर रेस्पो/प्रार्थीगण काश्त कर अपने परिवार का जीवकोपार्जन करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के पास अपीलांट/अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख०न० 848 है जिसकी पूर्वी मेर के सहारे प्रार्थीयान अपने उक्त खेतो पर आते जाते है। जिसे अपीलांट द्वारा रेस्पो० को आने जाने से रोकने पर ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत पेश किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट से जबाब प्रार्थना पत्र का प्राप्त किया जाकर तहसीलदार बौली से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर रेस्पो/प्रार्थीगण के खेतो पर आने जाने हेतु अपीलांट/अप्रार्थी की भूमि ख०न० 848 की पूर्वी मेर की और मे से 24 मीटर चौडाई जो लगभग 0.01 है० होती है कि प्रतिकर राशि राजकोष मे जमा कराने के पश्चात अपीलांट/अप्रार्थी को अदा करने की शर्त पर विधि अनुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है जो विधि के अनुरूप है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण/रेस्पो० द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत पेश कर रिलीफ चाही गई कि "घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी ख०न० 848 की पूर्वी मेड के सहारे प्रार्थीगण की खातेदारी ख०न० 840 तक हमेशा की तरह रास्ते को खुलासा रखे एवं उसमे प्रार्थीगण को आने जाने मे किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नही करे तथा नक्शा ट्रेस मे ख०न० 848 से 840 तक जो रास्ता दर्शाया गया है जिसमे यह नम्बर अंकित नही है उसमे नवीन नम्बर डलवाया जावे जिससे रास्ते को नवीन नम्बर से जाना जावे" उक्त तथ्य से जाहिर है कि प्रार्थीगण/रेस्पो० द्वारा केवल मात्र अपीलांट द्वारा रास्ते को अवरुद्ध नही करने की प्रार्थना चाही गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चाही गई प्रार्थना के विपरीत डीएलसी राशि का दो गुना राशि प्रतिकर के रूप मे जमा कराने की शर्त पर अपीलांट/अप्रार्थी के खेत मे से रास्ता प्रदान किया गया है। इसके साथ ही अधिनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस रिपोर्ट मे किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है केवल मात्र पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है। जबकि विधि के प्रावधान के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से कम स्तर के अधिकारी की रिपोर्ट मान्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है इसके साथ ही प्रार्थीगण/रेस्पो० द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत नही किया गया है। उक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

अतः अपील अपीलांत रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौली के मु0नं0 24/20 निर्णय दिनांक 3.7.23 को निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/रेस्पों की आराजीयात पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हो तथा रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता हो तो प्रार्थीगण/रेस्पों से धारा 251 ए के तहत निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट उभयपक्ष की मौजूदगी में तहसीलदार से तैयार करवाई जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(लक्ष्मी कांत बालोत)  
रसजस्व अपील प्रार्थीकारी  
सवाई माधोपुर